International Trade Fair (IITF) regularly during the past six yeas. As part of the 50th Anniversary Celebrations of India's Independence, the Embassy of India, Hanoi is organising an exclusive "Pride of India" Exhibition in January, 1998 in which leading Indian companies, both from public and private sectors are going to participate.

(d) *Indian Investment in Vietnam:* The Vietnamese economy is undergoing rapid transformation wth an increasing participation of private sector. Indian companies have shown interest in Vietnam. Major projects set up in Vietnam by Indian companies are listed below:

(1) Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has established a US $ 41 million joint venture with Petro Vietnam for offshore exploration in Vietnam.

(2) M/s Ansal Properties and Industries have undertaken a real estate development project in Vietnam through a joint venture company.

(3) M/s Nagarjuna Corporation have invested in a sugar plant.

(4) M/s KCP Limited, Chennai bagged a US$ 8 million contract for supply and installation of sugar plant for M/s Vina Sugar, a state-owned Vietnamese Corporation.

(5) M/s KEC Limited, Mumbai has formed a joitn venture for construction, supply and erection of steel towers. Total value of the project is US$ 2.727 million with Indian equity of US$ 1.636 million.

(6) Siva Plastics, Chennai intend to set up a joitn venture in Vietnam for manufacture of polybags. The total cost of the proejct is US$ 200,000 out of which the Indian company would contribute machineries worth US$ 120,000.

(7) Rajshree Sugars & Chemicals Ltd., Coimbatore have been licensed by the Vietnamese Government for making a 100% investment in a sugar plant.

(8) Several Indian companies (viz. PEC, RITES, Cimmco, Indian Rayon etc.) have established their presence in Vietnam.

There is no Vietnamese investment in india.

Improving Bilateral Relations with South Africa

176. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to improve bilateral relations with South Africa;

(b) if so, whether any steps have been taken by Government in that direction; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERWANI): (a) to (c) The close relations between India and south Africa are based on the pioneering role played by Mahatma Gandhi in establishing the foundations of the South African struggle; the sustained support provided by India to the struggle against apartheid; and the shared commitment to democracy in a multi-cultural society. Since the establishment of a democratic government in South Africa in may 1994, both countries have been engaged in an active programme of bilateral cooperation covering a wide range of activity. President Mandela paid two state visits to India in janaury 1995 and March 1997. Prime Minister visited South Africa in october 1997. Several high level visits have been exchanged, including that of our Vice President in may 1994 and of the Deputy President of South Africa in December 1996. A Joint Commission has been established and has met twice, several bilateral agreements have been concluded and bilateral trade has increased manifold. During President mandela's visit in march 1997 a historic Declaration on Strategic Partnership between India and South Africa was signed committing the two countries to a constructive partnership in the pursuit of their common objectives on strengthening bilateral relations, South-South Cooperation, preservation of the Gandhi heritage site in South Africa, UN reform, revitalisation of the Non-aligned Movement, etc. in his address to the South African Parliament on October 7, 1997 Prime Minister emphasised the need to

give this partnership a people's orientation through greater cooperation on developmental issues and through joint efforts to promote a democratic international order.

पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद

177 **श्री ओंकार सिंह लखावत:**
श्री डब्ल्यू अडौ सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पड़ोसी देशों के साथ हमारे कितने अनिर्णीत भूमि और समुद्रीय सीमा विवाद हैं;

(ख) वे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ भू-भागीय क्षेत्राधिकार, हथियारों, विस्फोटकों और स्वापक पदार्थों की सीमा पार से तस्करी के संबंध में हमारे विवाद हैं; और

(ग) विवादों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (ग) **पाकिस्तान**

जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 78 हजार वर्ग किलोमीटर भारतीय प्रदेश पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। सिर क्रीक में भी, भारत और पाकिस्तान के सीमा के संबंध में भिन्न-भिन्न मत हैं; और इसके अलावा, दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा का अभी भी सीमांकन नहीं हुआ है।

सरकार भारत और पाकिस्तान के सभी आपसी मसलों का शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए बचनबद्ध है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत पुन: आरम्भ हो गई है।

बंगलादेश तथा म्यांमार

बंगलादेश और म्यांमार के साथ हमारी भू-सीमा के सीमांकन का कार्य अधूरा है। बंगलादेश के साथ हमारी समुद्री सीमा का मसला भी अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

चीन

जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारतीय प्रदेश के लगभग 5,120 वर्ग किलेमीटर क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था।

भारत और चीन सीमा मसले के समाधान का कोई उचित, तर्क संगत और परस्पर रूप से स्वीकार्य हल निकालने की दिशा में कार्य करने के लिए बचनबद्ध हैं। दोनों देश सीमा मसले पर भारत-चीन संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) और भारत-चीन विशेष दल (ईजी) की रूपरेखा के अन्तर्गत बातचीत कर रहे हैं। सितम्बर, 1993 में संपन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शान्ति बनाए रखने से संबद्ध करार तथा नवम्बर, 1996 में संपन्न सीमा क्षेत्रों में अमन और शान्ति बनाए रखने से संबद्ध करार सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शान्ति बनाए रखने में योगदान करेंगे।

नेपाल और भूटान

भूटान के साथ हमारा कोई अनसुलझा सीमा विवाद नहीं है।

नेपाल के साथ, सीमा के सीमांकन का कार्य चल रहा है। यह कार्य 1981 में इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त तकनीकी स्तर की सीमा समिति (जेटी एल सी) द्वारा संचालित किया जा रहा है। जेटीएलसी के कार्य संचालित करने के दौरान, दोनों क्षेत्रों के छोटे खण्डों में सीमा को सीमांकित करने में कुछ कठिनाईयां आड़े आई हैं। ये खण्ड नारासाही-सूषता और कालापानी हैं।

नारासाही-सूषता क्षेत्र में, नेपाल ने नदियों के मार्ग परिवर्तन की समस्या के कारण भूमि के एक भाग पर अतिक्रमण किया है। इस पर जेटीएलसी के तहत चर्चा हुई थी तथा किसी प्रकार का संयुक्त स्थल सत्यापन संचालित करने से पूर्व, इस क्षेत्रों को फेटोग्राफ सर्वेक्षण करने का फैसला किया था। कालापानी का मसला उत्तर-पश्चिमी नेपाल के निकट उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ जिले में लगभग 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से संबंधित है। नेपाल इस पर अपना प्रदेश होने का दावा करता है और लिपु लेख को जाने वाले मार्ग पर कालापानी स्थित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस चौकी को खाली करने के लिए कहता है। इस पर वह अपना दावा सुगोली की 1815 की संधि के आधार पर इस कारण से जताता है कि यह क्षेत्र काली नदी के पूर्व में अब स्थित है। इस क्षेत्र में सीमा की सीध वास्तविक रूप से सुपरिभाषित है। जिसका सीमांकन विगत शताब्दी में किया जा चुका है।

जून, 1997 में प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान, यह फैसला किया था कि जेटीएलसी का संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू सी) पश्चिमी सीमा के सीमांकन के मसले का हल निकालेगा जिसमें कालापानी क्षेत्र भी शामिल है। संयुक्त तकनीकी स्तरीय सीमा समिति और संयुक्त कार्यदल के इस मसले को अपने हाथ में ले लिया है।